



महंगाई ने बढ़ाई मुसीबत टीके पर नासमझी



किरीट ए. चावड़ा

दूसरी कमांडिटी के दाम और बढ़ेंगे। यानी आगे भी आरबीआई के लिए ग्रोथ और महंगाई दर के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। कमांडिटी के अधिक दाम से उद्योग-धंधों पर भी बुरा



असर पड़ेगा क्योंकि उनके लिए कच्चे माल की लागत बढ़ जाएगी। इससे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और महंगे होंगे। इसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें पेट्रोलियम गुड्स और खाने-पीने की महंगाई दर शामिल नहीं होती। मई में यह पिछले 83 महीनों में सबसे अधिक रही। इसका मतलब यह है कि

खबर इतनी ही नहीं है। खुदरा महंगाई दर में खाने के सामान की महंगाई मई में 5.01 फीसदी रही, जो इससे पिछले महीने सिर्फ 1.96 फीसदी थी। इसमें खाने का तेल और दाल की कीमतों का बड़ा योगदान है। खाने के सामान के साथ पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की महंगाई से गरीबों पर सबसे अधिक चोट पड़ रही है। इससे दूसरी जरूरतों पर खर्च करने के लिए उनके पास कम पैसा बच रहा है। यही हाल रहा तो इससे खपत और घटेगी, जिसका ग्रोथ पर बुरा असर होगा। केंद्र और राज्य चाहें तो पेट्रोलियम गुड्स पर टैक्स घटाकर लोगों को फौरन महंगाई से राहत दे सकते हैं। पेट्रोल के दाम में 61 फीसदी और डीजल में 54 फीसदी टैक्स के मद में जाता है। इससे लोगों, कारोबारियों और रिजर्व बैंक को राहत मिलेगी, कर्ज सस्ता बना रहेगा, खपत को मजबूती मिलेगी। इसके साथ, केंद्र को आर्थिक गतिविधियां तेज करने के लिए राहत पैकेज लाने पर भी विचार करना चाहिए।

सरकार ने अपनी तरफ से यह स्पष्टीकरण देकर अच्छा किया है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन में नवजात बछड़ों का सीरम नहीं होता। सोशल मीडिया के जरिए फैली यह अफवाह महामारी की तीसरी लहर को रोकने के तमाम प्रयासों पर पानी फेर सकती है। हालांकि इसके मूल में आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल से मिले जवाब को बताया जा रहा है, लेकिन इस जवाब को कांग्रेस के एक नेता ने जिस अंदाज में ट्वीट किया, उससे इस विवाद ने एक अलग ही रूप ले लिया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद न केवल भारत बायोटेक और केंद्र सरकार की ओर से बल्कि ट्विटर पर सक्रिय जानकार लोगों की ओर से भी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश हुई। इससे यह साफ हुआ कि मामला आरटीआई के तहत हासिल किए गए जवाब का उतना नहीं, जितना उसे समझने में हुई चूक का है। वेरो सेल विकसित करने के लिए अगर बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है तो इसका

मतलब यह नहीं हुआ कि फाइनेल प्रॉडक्ट यानी वैक्सीन में भी यह सीरम होता है और न ही यह कि इसके लिए नवजात बछड़ों को मारा जाता है। कोवैक्सीन पोलियो, रैबीज और इन्फ्लुएंजा के टीकों में भी इसका इस्तेमाल दुनिया भर में होता रहा

रखता है कि मोदी सरकार ने कबूल किया है कि कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम होता है... यह सूचना पहले ही सार्वजनिक की जानी चाहिए थी। जाहिर है, सरकार विरोधी तेवर के साथ ही इसमें धार्मिक भावनाओं को लाने की परोक्ष कोशिश भी है।



है। मगर यहां मसला सिर्फ एक टेक्निकल मुद्दे को न समझने भर का नहीं, उसके राजनीतिक इस्तेमाल की मंशा का भी है। सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोलर की ओर से मिले जवाब को ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता का यह कहना मायने

आरटीआई के आधार पर वैक्सीन में धार्मिकता के सवाल को लाकर लोगों में वैक्सीन संबंधी हिचक को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छी बात यह रही कि अपने एक नेता की ओर से किए गए इस ट्वीट को कांग्रेस ने भी ज्यादा तूल नहीं दिया। उसने खुद को इस विवाद से अलग रखा। सभी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि वायर्स के खिलाफ लड़ाई को किसी भी रूप में बाधित करना आत्मघाती होगा। खासकर मौजूदा दौर, जब दूसरी लहर उतार पर है और तीसरी लहर आने में थोड़ा वक्त है, हमारी तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम है। इसी अंतराल में टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज करके हम तीसरी लहर के रूप में आने वाली विपदा को टाल सकते हैं। ऐसे में सबकी कोशिश टीकाकरण प्रक्रिया को यथासंभव तेज करने की ही होनी चाहिए।



जिगर डी वाढेर

पैथी कोई भी हो, मरीज का ठीक होना जरूरी

इलाज में एलोपैथी और आयुर्वेदिक दवाओं का एक साथ प्रयोग करके देखा गया। इनमें लगभग 93 हजार मरीजों को लंबे समय तक उपचार के लिए चुना गया। इससे मरीजों को बीमारी से उबरने में काफी कम समय लगा। इस तरह के प्रयोग के बाद यह निष्कर्ष सामने आया है कि चाहे एलोपैथी के ज्ञाता हों या फिर आयुर्वेद, होम्योपैथी के या फिर स्वास्थ्य महकमा, इन सभी को प्रयास इस बात की करनी चाहिए कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को मिलाकर एक छत के नीचे मरीज का इलाज कैसे संभव हो। प्राथमिकता मरीज का जीवन बचाना है, इसलिए अलग-अलग चिकित्सा पद्धति के साथ सफल प्रयोग पर

आयुर्वेदिक दवाओं की पहचान की है, जिन्हें एलोपैथिक डॉक्टर बड़े पैमाने पर लिखते हैं। वहीं, बीते सालों में डायबीटीज, कैंसर, किडनी व दिल की बीमारियों के लिए असरदार आयुर्वेदिक दवाएं विकसित करने का दावा किया

गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तहत आने वाले एनबीआरआई और सीआईएएमपी ने बीजीआर-34 नाम की आयुर्वेदिक दवा विकसित की है। इसे टाइप-2 डायबीटीज के इलाज में असरदार बताया गया है। वहीं, सेंट्रल कार्डिसल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस (सीसीआरएस) ने आयुर्वेदिक फॉर्म्युले से आयुष-क्यूओएल-2 सी नामक दवा बनाई

स्तन और सर्वाइकल कैंसर के मरीजों में किया जा रहा है। इसके अलावा साल 2019 में भोपाल एम्स के अध्ययन में आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक दवा फीफाट्रोल को स्टैफिलोकोकस प्रजाति के तीन बैक्टीरिया के खिलाफ बेहद प्रभावी पाया गया। स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया त्वचा, सांस और पेट संबंधी संक्रमण के लिए जिम्मेदार है। ये तो महज चंद उदाहरण हैं। आयुर्वेदिक दवाएं एलोपैथी की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स रोकने में और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी उपयोगी हैं। ऐसे में इनका एक साथ उपयोग कई जिंदगियां बचा सकता है। इसी के चलते साल 2018 में गुरुग्राम स्थित वरीय चिकित्सा संस्थान मेदांता-दि मेडिसिटी ने मेदांता- आयुर्वेद तक की

शुरुआत की है। भारत में यह पहली बार है, जब किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एलोपैथी और आयुर्वेद से एक साथ इलाज होगा। आधुनिक चिकित्सा और प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों के ऐसे सहयोगी प्रयासों से ही बेहतर तरीका इलाज संभव हो सकता है। इस सबके बावजूद जब पिछले दिनों बाबा रामदेव और आईएमए का विवाद सामने आया, तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इस मसले पर तर्क और उससे कहीं ज्यादा कुतर्क शुरू हो गए। बहरहाल, जब तक कोविड-19 का कोई पुख्ता इलाज नहीं मिल जाता, तब तक सभी पैथियों को इस बात पर अमल करना चाहिए कि कैसे वे आपस में मिलकर अधिक से अधिक जिंदगी बचा लें।



दिलाता है और शरीर को भी कई तरह के साइड इफेक्ट्स से बचाता है। आयुष मंत्रालय ने ऐसी कई

सरकारों से क्यों भिड़ रहा है सोशल मीडिया



हाल के दिनों में सोशल मीडिया कंपनियों का सरकार से टकराव बढ़ा है। खासकर मोदी सरकार के दूसरे टर्म में कई मसलों पर इन कंपनियों के सरकार से मतभेद हुए। कुछ मामले तो अदालत तक पहुंच गए। वॉट्सऐप से जुड़ा मसला कोर्ट में है। उधर, ट्विटर और सरकार के बीच विवाद भी दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ने मानकों का पालन

दिलचस्प पहलू यह है कि सत्ता में बैठे जिन लोगों से सोशल मीडिया का टकराव हुआ, उनमें अधिकतर ऐसे हैं जिनके लिए कभी सोशल मीडिया सत्ता की सीढ़ी बना था। भारत में भी 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की थी, तो उन्होंने इसके लिए सोशल मीडिया को भी मददगार बताया था। नया नहीं है यह टकराव भारत सहित कई देशों में सोशल मीडिया के साथ टकराव के पीछे मुख्य कारण यह है कि हर सरकार अपने-अपने स्तर पर नियम बना रही है। भारत ने भी हाल ही में सोशल मीडिया के लिए नए कानून बनाए हैं। जैसे यह टकराव अचानक शुरू नहीं हुआ। यूपीए-2 के समय ही सोशल मीडिया पर अंकुश

लागने पर पहला टकराव हुआ आईटी एक्ट की धारा 66ए को लेकर। हालांकि, तब सोशल मीडिया कंपनियों से अधिक इसका उपयोग करने वाले यूजर्स पर अंकुश लगा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खत्म कर दिया। फिर जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तो सबसे पहले 2016-17 में टकराव हुआ। तब केंद्र सरकार ने नए कानून बनाने की भी पहल की थी, जिसमें कहा गया कि सभी सोशल मीडिया कंपनियों को भारतीय यूजर्स का डेटा भारत में ही रखना होगा और उन्हें यहां अलग से लाइसेंस भी लेना होगा। सरकार का तर्क है कि ये कंपनियां देश के अंदर कानूनी प्रक्रिया से इसलिए बच जाती हैं, क्योंकि इन्होंने लाइसेंस देश के अंदर से नहीं लिया है। लेकिन इसके लिए भी सोशल

मीडिया कंपनियां आज तक तैयार नहीं हुई हैं। इसके बाद सरकार का टकराव फेसबुक से हुआ। इस सोशल मीडिया कंपनी पर राजनीतिक दलों के साथ काम करने वाली कैब्रिज एनालिटिका के साथ मिलकर चुनावी लाभ के लिए डेटा लीक करने का आरोप लगा था। यह भी आरोप लगा था कि फेसबुक अपने प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है। इस खुलासे के बाद मोदी सरकार ने फेसबुक को चेतावनी दी थी कि अगर उसने डेटा चोरी के जरिए चुनावों को प्रभावित करने का कोई प्रयास किया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग को भी नोटिस भेजा था। लेकिन

बाद में फेसबुक के भरोसा दिलाने के बाद विवाद शांत हो गया। 2019 में आम चुनाव से पहले ट्विटर से भी टकराव हुआ। तब चुनाव से ठीक पहले शिकायत मिलने के बाद संसदीय समिति ने सोशल मीडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस भेजा था। आरोप था कि दक्षिणपंथी विचारों को सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर जान-बूझकर टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद अब सामने आया है नया आईटी कानून, जिसे लेकर अभी सारा विवाद है। केंद्र सरकार और वट्सऐप में इन दिनों तनातनी चल रही है। सरकार इस सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर आने वाले हेट और फेक कंटेंट पर अंकुश लगाने के लिए आईटी एक्ट में बदलाव कर संदेशों को ट्रैक



भूपेन्द्र पटेल

करने का अधिकार चाहती है। लेकिन वट्सऐप ने कहा है कि चूँकि वह यूजर्स की निजता से समझौता नहीं कर सकती, इसलिए वह इसके लिए तैयार नहीं है। गूगल ने भी सरकार की बात मानी, लेकिन डेटा साझा करने के मुद्दे पर अभी गोलमोल उत्तर ही दिया है। उधर, सरकार ने आरोप लगाया कि ट्विटर कानून ही मानने को तैयार नहीं है। कंपनियों का अपना तर्क है कि विश्व के अलग-अलग देशों में सरकारें नियमों का हवाला देकर फ्री स्पीच पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। विश्व के कई देशों में इसकी मिसाल भी देखी। इसी चिंता के बीच अभी जी-7 देशों के सम्मेलन में ताकतवर देशों ने लिखित प्रस्ताव पास किया कि वे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन (ऑनलाइन और ऑफलाइन)

जान लीजिए अगले महीने से बदलने वाले टीडीएस के नियम, वरना हो सकती है बड़ी परेशानी!

New TDS Rules: फाइनेंस एक्ट 2021 के लागू होने के बाद टीडीएस में कुछ जरूरी बदलाव (TDS Rules Changing From 1st July) किए गए हैं। ये बदलाव नया सामान खरीदने (TDS Rules for goods purchase) और आईटीआर फाइल (TDS Rules for non itr filers) नहीं करने वालों से जुड़े हैं। 1 जुलाई से ये नए बदलाव प्रभावी हो जाएंगे। सामान खरीदने के टीडीएस से जुड़े नियम बदलेंगे और साथ ही आईटीआर फाइल नहीं करने वालों पर पहले से अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। आइए जानते हैं। 1 जुलाई से क्या-क्या बदलेगा। सामान की खरीद लगने वाला टीडीएस हाल ही में सेक्शन 194Q जोड़ा गया है। यह सेक्शन किसी सामान को खरीदने के लिए पहले से ही तय कीमत के भुगतान पर लगने



(टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) 50 हजार रुपये से ज्यादा है तो भी टीडीएस कटौती 5 फीसदी की दर के की जाएगी। आधार-पैन लिंक कराना ना भूलें अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जिन्होंने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। 31 मार्च को सीबीडीटी ने आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख को 30 जून तक बढ़ाया था। हालांकि, टैक्स डिपार्टमेंट के



कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि ये आखिरी बार है जब लिंकिंग की तारीख बढ़ाई गई है। अभी भी जो लोग आधार-पैन लिंक नहीं करवाएंगे, उन पर भारी-भरकम जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे करें स्टेपस चेक www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। लेफ्ट साइड (बायीं ओर) में 'क्विक लिंक्स' में 'लिंक आधार' (Link Aadhaar) पर क्लिक

हो सकती है। अगर SMS के माध्यम से पैन-आधार लिंक कराना चाहते हैं तो UIDPAN <SPACE> 12 अंकों का आधार नंबर <SPACE> <10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा। उदाहरण के लिए, UIDPAN 111122223333 AAAA9999Q ऐसे ऑनलाइन लिंक करें आधार-पैन <https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home> पर जाएं। बायीं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में 'L i n k Aadhar' पर क्लिक करें। अब जो पेज खुलेगा, उसमें PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है। अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- 'I have only year of birth in Aadhaar card'। इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें। इसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें शो होगा कि PAN, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है। ऑफलाइन भी है तरीका P A N सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी PAN और आधार को लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म 'Annexure-1' भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी। यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है। आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा। यह शुल्क, लिंकिंग के समय PAN या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा।

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सस्ते दामों में प्लॉट दिलाने का वादा कर 50 करोड़ की ठगी

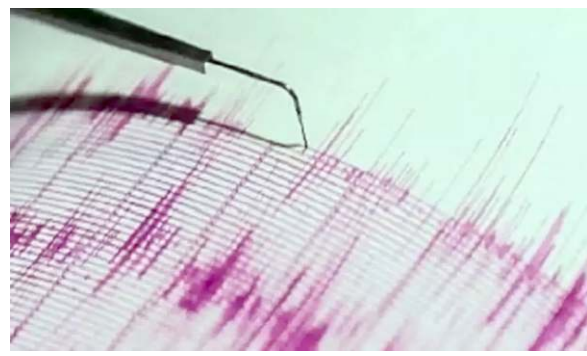


लखनऊ, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर क्वेडा एक्सप्रेस सिटी नाम से जमीन दिलवाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से 50 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। रायबरेली जनपद के रहने वाले एक पीड़ित ने कंपनी के खिलाफ

तलाश में जुटी है। पकड़े गए आरोपियों के पास से चार लैपटॉप, जमीन से संबंधित दस्तोत, तीन लजरी कार, 18 रबर की मोहरें, स्वाइप मशीन, एटीएम कार्ड और अन्य सामान बरामद किया। सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर लोगों को फंसाया एडीसीपी पूर्वी कासिम आब्दी ने बताया कि रायबरेली जनपद निवासी प्रदीप कुमार को कुछ समय पहले फेसबुक के माध्यम से विभूतिखंड विनम्रखंड स्थित क्वेडा कंपनी के बारे में पता चला था। विज्ञापन में दिए गए नंबर पर संपर्क करने पर उनको पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सस्ते दाम में प्लॉट दिलवाने की बात कही गई। इसके बाद वह कंपनी के दफ्तर

को कुछ शक हुआ। उन्होंने अपने स्तर से जब छानबीन की तो पता चला कि उक्त कंपनी जमीन के नाम पर कई लोगों से ठगी कर चुकी है। इस पर पीड़ित ने अपने दिए गए रुपये वापस मांगे तो कंपनी के लोगों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए कंपनी के दफ्तर से भगा दिया। पीड़ित ने बुधवार को दर्ज करवाई रिपोर्ट, पांच गिरफ्तार अपने साथ हुई इस ठगी के संबंध में पीड़ित ने बुधवार को विभूतिखंड थाने में कंपनी के डायरेक्टर रेख चंद्र मोर्य, रमा यादव, अनिल यादव, मीनाक्षी तिवारी, पूनम तिवारी, आनंद मोर्य, रजनीश मोर्य, अरुणेश प्रताप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई।

असम में देर रात आया 4.2 तीव्रता का भूकंप का झटका, पूर्वोत्तर में 24 घंटे में चौथा झटका



तेजपुर, असम में शनिवार आधी रात के बाद 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। जान-माल के किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। पूर्वोत्तर के क्षेत्र में 24 घंटे के दौरान यह भूकंप का चौथा झटका रहा। असम में देर रात एक बजकर 7 मिनट पर आए भूकंप का केंद्र तेजपुर से 39 किलोमीटर पश्चिम में जमीन से 30 किलोमीटर की गहराई में रहा। एक दिन पहले ही यहीं सोनितपुर में 4.1 तीव्रता का झटका महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र तेजपुर से 36 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की तरफ जमीन से 22 किलोमीटर की गहराई में रहा। इसका केंद्र मोइरांग से 39 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में न्यांगार की सीमा के पास जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में रहा। इससे पहले पूर्वोत्तर में एक के

जम्मू-कश्मीर पर महामंथन-विपक्षी नेताओं से मिल सकते हैं PM मोदी, महबूबा मुफ्ती बोलीं- फोन आया है, लेकिन नहीं लिया कोई फैसला

नई दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने सहित राजनीतिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने की केंद्र की पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को वहां के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। यह बैठक केंद्र द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन करने की घोषणा के बाद से इस तरह की पहली कवायद होगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय नेताओं के भाग लेने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी (जेकेएपी) के अल्टाफ बुखारी



और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन को चर्चा के लिए आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र के साथ बातचीत की संभावना के बारे में पूछे जाने पर, माकपा नेता और पीपुल्स अलायंस फॉर गुप्कर डिक्लेजेशन (पीएजीडी) के प्रवक्ता एम वाई तारिगामी ने

कहा कि नयी दिल्ली से कोई संदेश नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा होता है, तो इसका स्वागत किया जाएगा। तारिगामी ने श्रीनगर से कहा कि हमने केंद्र के साथ सार्थक जुड़ाव के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए हैं। हालांकि मुझे किसी बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अगर ऐसा होता है, तो इसका स्वागत किया जाएगा। पीएजीडी जम्मू कश्मीर में कुछ पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी शामिल हैं, जो केंद्र के अगस्त 2019 के फैसलों के बाद बनाया गया था। भाजपा और कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाइयों के भी इन चर्चाओं का हिस्सा होने की संभावना है, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश में सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।

बंगाल में अब भाजपा में मची भगदड़, TMC में हुई 300 BJP वर्कर्स की वापसी, गंगाजल से हुआ शुद्धीकरण

बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जहां ममता की टीएमसी में भगदड़ मची हुई थी, वहीं अब उलटा भाजपा के साथ हो रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी की फिर से सरकार बनने ही टीएमसी छोड़ भाजपा में गए नेताओं और कार्यकर्ताओं की घर वापसी शुरू हो गई है। मुकुल रॉय की घर वापसी के बाद न सिर्फ कई नेता कतार में हैं, बल्कि अब ग्राउंड लेवल के भाजपा कार्यकर्ता भी टीएमसी में लौटने लगे हैं। लेटेस्ट घटनाक्रम में बंगाल के बीरभूम जिले में एक साथ 300 भाजपा कार्यकर्ता शुक्रवार को टीएमसी में वापस लौटे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस



कार्यालय के सामने कम से कम 300 भाजपा समर्थक भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनकी मांग थी कि उन्हें टीएमसी में वापस लिया जाए। हालांकि, बाद में उन सभी को टीएमसी में शामिल कराया गया और गंगाजल छिड़क कर उनके दिमाग का शुद्धीकरण किया गया।

मंडल ने कहा कि हम चाहते हैं कि टीएमसी में हमें वापस ले लिया जाए। हमने अपने गांव के विकास को रोक दिया है। भाजपा में शामिल होने से हमें फायदा के बदले नुकसान हुआ। हम अपनी इच्छा से दोबारा वापस आना चाहते हैं। हमें जब तक वापस नहीं लिया जाता, तब क हम धरने पर बैठें रहेंगे। इन तीन सौ कार्यकर्ताओं को टीएमसी का झंडा सौंपने वाले बानाग्राम के तृणमूल पंचायत प्रधान तुषार काम्रत मंडल ने कहा कि ये लोग पिछले कुछ दिनों से हमारी पार्टी में शामिल होने का अनुरोध कर रहे थे। आज वे पार्टी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और वापस लेने की अपील की।

सपा नेता उमेद पहलवान दिल्ली से गिरफ्तार, बुजुर्ग से मारपीट को लेकर किया था फेसबुक लाइव

गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में कथित तौर पर एक बुजुर्ग के साथ मारपीट मामले में भ्रामक तरीके से फेसबुक लाइव करने के आरोपी सपा नेता उमेद पहलवान को गाजियाबाद पुलिस ने शनिवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कई दिन से उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने बताया कि उसे दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास

से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को मोबाइल लोकेशन के आधार पर शनिवार सुबह आरोपी के दिल्ली में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज उसे दबोच लिया। पुलिस आरोपी को लेकर थोड़ी देर में गाजियाबाद पहुंच रही है। जानकारी के अनुसार, मारपीट और अभद्रता के शिकार बुजुर्ग अब्दुल समद

और उनके दोनों बेटों को लेकर गाजियाबाद निवासी उमेद पहलवान गायब हो गया था। परिजनों के अनुसार, उमेद पहलवान अब्दुल समद और उनके दोनों बेटों को लेकर दिल्ली जाने की बात कहकर निकला था। माना जाता है कि पुलिस का शिकंजा कसने के साथ ही वह बचता फिर रहा था। उधर, सुरक्षा की दृष्टि से शुक्रवार को भी अब्दुल समद के घर पर पुलिस पिकेट तैनात रहा। वहीं, अनूपशहर पुलिस महामारी अधिनियम के मुकदमे में अज्ञात 100 लोगों को चिह्नित करने के लिए सभा का वीडियो खंगाल रही है। गौरतलब है कि 5 जून को लोनी क्षेत्र में अनूपशहर के मोहल्ला मीरा निवासी अब्दुल समद के साथ मारपीट हुई थी। पीड़ित पक्ष

के अनुसार, 5 जून को अब्दुल समद सैफी (72) अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए गाजियाबाद गए थे। वहां से एक ऑटो में सवार हुए, जिसमें चार युवक सवार थे। आरोप है कि युवकों ने अब्दुल समद के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की। गाजियाबाद पुलिस द्वारा ताबीज बनाकर देने के बाद हुए विवाद के चलते अब्दुल समद के साथ

मारपीट किए जाने की बात कहते हुए अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभा करने पर दर्ज हुआ था केस : उमेद पहलवान ने अब्दुल समद के साथ बुधवार की रात अनूपशहर पहुंचकर उसके मोहल्ले में सभा का आयोजन किया और उसे फेसबुक लाइव किया। अनूपशहर पुलिस ने उमेद, ताजुद्दीन, फिरोज मेवाती,



मोहल्ला मीरा सुनसान है।

बी. वोक इंटीरियर डिजाइन में प्रवेश



आर्किटेक्ट धीरज सल्लोत्रा (प्रधान अध्यापक) ठाकुर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, मुंबई

योजना अध्ययन की स्थानीय और वैश्विक दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण मिशन की ओर उन्मुख है। डिजाइन अध्ययन के युवा, नवोदित, इच्छुक छात्र बेहतरीन वास्तुकला और डिजाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं जो राज्य और देश के समग्र सतत विकास के अनुरूप है।

बी. वोक इंटीरियर डिजाइन के लिए पात्रता: इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में शामिल होने के लिए छात्र की पात्रता होगी-



एचएससी किसी भी स्ट्रीम (विज्ञान / वाणिज्य / कला) या समकक्ष से उत्तीर्ण या S.S.C + दो साल का पूर्णकालिक डिप्लोमा या तीन साल का अंशकालिक डिप्लोमा। और- संस्थान द्वारा आयोजित एक प्रवेश (एपीट्यूड टेस्ट) परीक्षा। एपीट्यूड टेस्ट में स्कोर करने में प्राथमिक जोर उम्मीदवार की ड्राइंग, कल्पना और अवलोकन कौशल पर होता है।

डॉ कृष्णा चौहान द्वारा मिस बॉलीवुड ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2021 का सफल आयोजन

यूपी की दीप्ति तिवारी रहीं विनर, खुशबू शर्मा व पीहू ठाकुर हुई रनर अप

मुम्बई : कोरोना महामारी से व्याप्त इस संकट काल में लंबे समय तक लागू लॉकडाउन के बाद अब लोगों का जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। लोग अपने अपने काम धंधे पर वापस लौटने लगे हैं। यही स्थिति बॉलीवुड में भी देखने को मिल रही है। बड़े प्रोडक्शन हाउस के बाद अब नए बैनर भी अपने प्रोजेक्ट की शूटिंग में निकल पड़े हैं। ऐसे हालात में मिस बॉलीवुड ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2021 का सफल आयोजन आज 15 जून को किया गया।



रहीं वहीं खुशबू शर्मा व पीहू ठाकुर हुई रनर अप। गौरतलब है कि दीप्ति तिवारी पिछले 20 साल से मुम्बई में रहकर कई धारावाहिकों और फिल्मों में काम किया है। फर्स्ट रनर अप खुशबू शर्मा इंदौर की रहने वाली हैं व बॉलीवुड में न्यू फेस हैं। 2nd रनर अप पीहू ठाकुर उत्तराखण्ड की हैं जो एक्टिंग के साथ साथ प्रिंट एंड शूट में भी व्यस्त रहती हैं। डॉ. कृष्णा चौहान का यह सातवां अवार्ड था। उन्होंने इससे पहले 6 अवार्ड समारोह करवाये हैं। इससे पूर्व कृष्णा चौहान ने दिसम्बर 2019 में बॉलीवुड लीजेंड एवार्ड और फरवरी 2020 में बॉलीवुड आइकोनिक एवार्ड करवाया था। सितंबर में मिस

बॉलीवुड ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2020, दिसम्बर 2020 में लीजेंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड, बॉलीवुड लीजेंड अवार्ड, फरवरी 2021 में बॉलीवुड आइकोनिक अवार्ड फंक्शन का सफल आयोजन किया था। कृष्णा चौहान फाउंडेशन के अंतर्गत वह अगले माह जुलाई में "लेजेंड दादासाहेब फाल्के एवार्ड 2021" फंक्शन करा रहे हैं। आपको बता दें कि निर्देशक कृष्णा चौहान बॉलीवुड में पिछले 18 वर्षों से फिल्म मेकिंग जैसी जटिल विधा को आत्मसात कर रहे हैं। इससे पहले कृष्णा की एक शार्ट फ़िल्म को राज्य स्तर पर सराहना मिली है जो कि सामाजिक मुद्दे पर बनी थी। इसके अलावा कृष्णा चौहान ने दो फ़िल्म की भी तैयारी कर ली है। कृष्णा चौहान फ़िल्म डायरेक्टर होने के साथ-साथ जनहित में समाजसेवा के विभिन्न कार्यों में भी लिप्त रहते हैं। साथ ही एक म्यूजिक कंपनी लांच करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड में कृष्णा चौहान का स्तबा और कद बड़ा हो चला है। अब वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डायरेक्टर कृष्णा चौहान का उनके नाम से कृष्णा फाउंडेशन तो है ही, उनकी कृष्णा चौहान नामक एड एजेंसी भी है। मिस बॉलीवुड ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2021 लगातार दूसरे साल आयोजित करके इसके फाउंडर व डायरेक्टर कृष्णा चौहान बेहद उत्साहित हैं, उन्होंने सभी विनर व रनर अप को मुबारकबाद पेश की है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हाउसिंग सोसाइटियों में बनेंगे चार्जिंग स्टेशन, आदित्य ठाकरे ने दिया प्रस्ताव



मुंबई, महाराष्ट्र में बढ़ते प्रदूषण और ईंधन के दाम के मद्देनजर अब महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए होने वाली चार्जिंग की समस्या को कम करने के लिए राज्य की हाउसिंग सोसाइटियों में चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही इस प्रस्ताव पर अमल शुरू हो जाएगा। राज्य के शहरों में प्रदूषण को कम करने के संदर्भ में शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन किया गया था। जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की थी। इसी बैठक में आदित्य ठाकरे ने हाउसिंग सोसायटी में चार्जिंग पॉइंट्स बनाने का सुझाव दिया था। ज्यादा से ज्यादा लोग करें इस्तेमाल ठाकरे ने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी

है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर भी जब ऐसे वाहनों को खरीदा जाए तब आर्थिक प्रावधानों की वजह से आने वाली दिक्कतों को भी समय से हल किया जाना चाहिए और नियमों में जरूरी बदलाव भी होने चाहिए। मसौदा तैयार करने का आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पर्यावरण मंत्री के इस प्रस्ताव को लेकर जल्द से जल्द मसौदा तैयार करने का आदेश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पुरुष का काम करना है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सड़क पर जगह देनी होगी। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण भागों में किस तरह से चार्जिंग स्टेशन को सुविधाजनक रूप से स्थापित किया जा सकता है इन तमाम बातों पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए।

अनलॉक हो रहे राज्य...तो कब से खुलेंगे स्कूल? जानें क्या है राज्यों का प्लान



नई दिल्ली, कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड समेत देश के अलग-अलग राज्यों में जनजीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है। ऐसे में लोगों के मन में अब यह सवाल उठ रहा है कि बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज कब से खुलेंगे। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही राज्य सरकारों अब स्कूल खोलने को लेकर घोषणाएं करेंगी। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल मार्च से ही सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। स्कूलों को खोलने को लेकर राज्य सरकारों अपने स्तर पर फैसला करेंगी। आइए जानते हैं स्कूलों को खोलने को लेकर विभिन्न राज्यों में क्या स्थिति है। पूरे भरोसे के बाद ही लेंगे स्कूल खोलने का फैसला डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि स्कूलों को फिर से खोलने से पहले कई फैक्टर्स और पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि कई देशों में स्कूल खोलने गए लेकिन संक्रमण बढ़ने के बाद उन्हें फिर बंद करना पड़ा। डॉक्टर पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस जैसे रूप बदल रहा है, उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आगे चलकर यह बच्चों को अभी की तरह ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए स्कूल खोलने का फैसला तभी लिया जाएगा जब पूरा भरोसा हो जाएगा कि महामारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। UP में 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल यूपी सरकार ने 1 जुलाई से प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। इस दौरान स्कूलों में सिर्फ प्रशासनिक काम होंगे। बच्चों को अभी स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। स्कूल में सिर्फ टीचर और अन्य स्टाफ ही आएंगे। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन ही जारी रहेगी।

लोगों की लापरवाही से तीसरी लहर आ सकती है-टोपे



मुंबई, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शुक्रवार को कहा कि यदि लोगों ने साफ-सफाई कायम रखने और मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन नहीं किया तो कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका है। मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में कम से कम 5,000 मौतें हुई हैं, जिनके बारे में पता नहीं चल पाया। इनसे संबंधित सारी जानकारी के सत्यापन के बाद संपूर्ण तालिका में इन्हें शामिल किया जाएगा। उन्होंने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल से कहा कि सड़कों पर की भीड़ नहीं बल्कि "लोगों के मास्क न पहनने और स्वच्छता नियमों का पालन नहीं करने" से तीसरी लहर आने का खतरा है। टोपे ने कहा, "कोई भी तीसरी लहर के बारे में सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन मास्क पहनने और उचित व्यवहार करने से हम इसके आगमन को टाल सकते हैं और इसके प्रभाव को न्यूनतम रखा जा सकता है।" टोपे ने कहा, "दूसरी लहर से स्वास्थ्य प्रणालियां बहुत प्रभावित हुईं और लड़खड़ा गईं। राज्य में लगभग 5,000 मौतें होने की आशंका है, जिनके बारे में जानकारी नहीं मिली। इनसे संबंधित सूचना का सत्यापन पूरा होते ही समग्र रिपोर्ट में इन्हें शामिल कर लिया जाएगा।"

KAANT FOODS
 Manufacturer of Khakhra & Dry Bhakri in Various Flavor
 Khakhra & Dry Bhakri is a thin cracker common in the Gujarati and Rajasthani cuisines of western India, especially among Jains. It is made from mat bean, wheat flour and oil. It is served usually during breakfast. Khakhras are individually hand-made and roasted to provide a crunchy and healthy snack that can be enjoyed with a selection of spicy pickles and sweet chutneys.
 20, 1st Floor, Sarvodaya Society, Opp. Hotel Oasis, Nr. Umia Dham Temple, Surat-395006. Gujarat, India.
 Email : kaantfoods@gmail.com Mob : 9825770072
 Web : www.kaantfoods.com

मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ेगा, बीजेपी-कांग्रेस-एनसीपी-सपा के विरोध के बाद पीछे हटी शिवसेना

मुंबई, प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर चौतरफा धिरी शिवसेना की तरफ से मेयर किशोरी पेडणेकर ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि मुंबईकरों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं लादा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंबई में एक साल तक प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। पेडणेकर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का सिर्फ प्रस्ताव आया है, उसे मंजूरी नहीं मिली है। बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर विपक्षी दलों भाजपा, कांग्रेस, राकांपा, सपा एवं आम आदमी पार्टी ने शिवसेना पर जोरदार हमला बोला, जिसके कारण शिवसेना बैंकफुट पर आ गई। भाजपा एवं कांग्रेस तो इसे अभी से चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करने लगी है। बीएमसी कानून के तहत प्रॉपर्टी टैक्स में हर पांच वर्ष बाद सुधार किया जाता है। 2015 में इसमें सुधार किया गया था। उसके बाद वर्ष 2020 में ही इसमें सुधार होना था, लेकिन कोरोना संकट के कारण राज्य सरकार ने वृद्धि को स्थगित कर दिया था। जून 2021 में उसमें रेडरिक्शन दर के अनुसार 14 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव बीएमसी प्रशासन ने स्थायी समिति में पेश किया है। धिरी शिवसेना पर भाजपा का हमला प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर भाजपा ने शिवसेना को होटल मालिकों और बिल्डरों की हितेषी

Jay Kuber CONSULTANCY
 PERSONAL LOAN, CONSUMER LOAN, HOME LOAN, MORTGAGE LOAN, CAR LOAN, MUDRA LOAN, INSURANCE, PANCARD
 Chintan Jiyan 99040 77991, Kishan Kyada 99040 77990
 jaykuber1997@gmail.com
 D-2080, 2nd Floor, Central Bazar, opp Varachha Police Station, Minibazar, Varachha, Surat